1- सरकार द्वारा बंद किए 18 OTT प्लेटफॉर्म्स

चर्चा के क्यों :– केंद्र सरकार के द्वारा 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लीलता फैलाने के कारण बंद किया गया । कोरोना के समय वल्गर कंटेंट में 1200% से ज्यादा वृद्धि हुई। 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के इस निर्णय से OTT पर प्रश्न उठता है की इसका सोसाइटी पर कैसा असर पड़ता है. अश्लील कंटेंट समाज के लिए किस प्रकार घातक है. OTT के माध्यम से पोर्न कंटेंट का जाल किस तरह फैला और OTT प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है।

theglobalstatistics.com ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार भारत में 2024 तक लगभग 45 करोड़ OTT सब्सक्राइबर्स हैं। वर्तमान में देश में कुल 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सक्रिय हैं और अभी देश में डिज्नी हॉटस्टार टॉप OTT प्लेटफॉर्म है। जिसका मार्केट पर कब्जा 41% है। ये 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफार्म से जिनकी जानकारी सरकार को है इनके अलावा कई छोटे OTT प्लेटफॉर्म भी हैं जिनके बारे कोई जानकारी नहीं हैं यह प्लेटफॉर्म क्या दिखाते हैं जिस प्रकार का कंटेंट देते है तभी पता चलता है जब इनसे जुड़ी कोई शिकायत सरकार तक पहुचती है।

KPMG (क्लिनवेल्ड पीट मारविक गोएर्डेलर) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ओटीटी पर पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील कंटेंट 2016 से 2020 के दौरान 1200% से ज्यादा बढ़ा। इसी समय छोटे प्लेटफॉर्म भी 'इरोटिक कंटेंट' (पोर्न) परोसते रहे ।

समाज और बच्चों को कैसे प्रभावित करता है :–

इंपल्सिविटी के द्वारा :–ओटीटी में दिखाए गए कंटेंट में वल्गैरिटी, न्यूडिटी और ड्रग एब्यूज अधिक होता है और इसको ग्लैमराइज भी अधिक किया जाता है जिससे बच्चे और समाज इसी प्रकार की जिंदगी पसंद करने लगते है।

सोशल मॉरल वैल्यू खत्म होती है:– ओटीटी पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, टीचर स्टूडेंट अफेयर और यहां तक कि फैमिली रिलेशनशिप मनोरंजन के नाम पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी चीजों को बच्चे वास्तविक समझ बैठे हैं और अपने जीवन में इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज की मोरल वैल्यूज और पारिवारिक वैल्यूज kum हो रही है

साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा :– ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाला कंटेंट इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एक एपिसोड को देखने के बाद दूसरे एपिसोड को देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है
और दूसरा एपिसोड देखने की तीव्र इच्छा होती है। जब ऐसे कंटेंट के संपर्क में लंबे समय तक रह जाता है और एक रात में कई एपिसोड देखे जाते हैं तो इससे प्राकृतिक नींद समाप्त हो जाती है जिससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का खतरा रहता हैं।

मनोरंजन की दुनिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है इन्हें :–

Central Board of Film Certification (CBFC) भारत में थिएटर्स में रिलीज होने वाली फिल्मों के कंटेंट रेगुलरेट करती है, तो वहीं टीवी और ओटीटी पर देखने वाले कंटेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के तहत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा रेग्यूलेट किया जाता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है

ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 में बनाया गया जिसके अनुसार नेटफ्लिक्स और वूट जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने ओटीटी पर 5 तरह के कंटेट न दिखाने की सहमति बनाई । जिनमे मुख्य थे :– चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कंटेंट. राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान करने वाला कोई कंटेंट. धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट. ऐसा कोई कंटेंट जिस पर अदालत ने रोक लगाई हो।

आपत्तियां आने के बाद सरकार ने इस रेगुलेशन कोड को काफी नहीं माना और निगरानी के नए नियम बनाए। वर्तमान में ओटीटी में कंटेंट की निगरानी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के द्वारा की जाती है। जिसके नियमों के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट का क्लासिफिकेशन, ऐज रेटिंग और सेल्फ रेगुलेशन का खुद पालन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 एक्ट की धारा 67, 67A और 67B के तहत सरकार पेश किए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक करती है।

2- भारत और ब्राज़ील '2+2 वार्ता

चर्चा में क्यों :– भारत और ब्राज़ील ने '2+2 वार्ता का आयोजन किया । दोनों देशों के मध्य यह पहली इस प्रकार की वार्ता है

2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में , रक्षा व विदेश मंत्रि आपस में मिलते है अन्य देश जिनके साथ भारत की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की जाती है :– संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान. 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने मध्य :– ऊर्जा, खनिज, प्रौद्योगिकी, व्यापार में वृद्धि, और आतंकवाद-रोधी मुद्दे पर चर्चा हुई।

भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय संबंध :–

2006 से भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदार है. दोनों देश कई अंतरराष्ट्रीय समूह में साथ सदस्य है जैसे :– संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, IBSA (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का समूह), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ।
G4 समूह :– ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का एक है। G4 समूह का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे का समर्थन करना है।

भारत और ब्राजील अंतरिक्ष में सहयोग की नीति पर काम करते है जिसके तहत 2021 में इसरो ने ब्राज़ील का अमेजोनिया-1 नामक उपग्रह लॉन्च किया ।

भारत और ब्राजील के मध्य व्यापार 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत, ब्राज़ील का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश ।

भारत और ब्राजील के मध्य जैव-ईंधन में सहयोग की नीति जिसके तहत ब्राज़ील विश्व में जैव ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत इसमें ब्राजील की मदद करता है।

भारत और ब्राजील के मध्य व्यापार निगरानी तंत और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर पर रणनीतिक वार्ता का आयोजन नियमित रूप से होता रहता है जिससे आपसी संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका दोनों देश निभाते है।

3- लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022"

चर्चा में क्यों :– "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII/gender inequality index) 2022" संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया गया

GII 2022 को UNDP की "मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" में शामिल किया गया है। हाल ही में, मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" को "ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजनिंग को-ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड" शीर्षक से जारी किया गया है।

लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) :– महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को दर्शाने वाला एक मापन है।
असमानता को तीन आयामों या मानदंडों पर मापा जाता है:

प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health): इसके तहत मातृत्व मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही महिला प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक को भी सामिल किया जाता है ।

महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment): संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात देखा जाता है साथ ही कम-से-कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष आबादी संकेतकों का इस्तेमाल भी किया जाता है ।

श्रम बाजार (Labour market): महिला एवं पुरुषों की श्रम बल भागीदारी का मापन किया जाता है साथ ही महिला और पुरुष श्रम बाजार सूचकांक को भी देखा जाता है ।

GII 2022 के मुख्य बिंदु :–

2022कुल 193 देशों को लैंगिक असमानता सूचकांक में सामिल किया गया । डेनमार्क को सर्वोच्च स्थान/रैंकिंग प्राप्त है। दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमश: नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। 193 देशों में भारत को 0.437 स्कोर के साथ 108व स्थान प्राप्त हुआ । जबकि 2021 में भारत को 122व स्थान प्राप्त हुआ था (191 देशों में) ।
भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन :– भूटान (80); श्रीलंका (90); और मालदीव (76) ।

कैसे निर्धारित किया जाता है :–

इसके अंतर्गत 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है।
जहां 0 का आशय महिला और पुरुष के बीच समानता से है। वहीं, 1 पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों या संकेतकों में व्यापक असमानता को दर्शाता है।

भारत द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्य :–

1.लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण ।

2.महिलाओं की सेफ्टी, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 'मिशन शक्ति' योजना ।

3.2020 में सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया ।

4.वेतन संहिता 2019 के तहत समान कार्य के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते समय महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं ।